CPI(M)

जन जोहार झारखण्ड

अंक–08 मासिक बुलेटिन जनवरी 2023

असहमति की संस्थागत हत्या का विरोध करें

संपादकीय ....

राज्य में पार्टी को जनोन्मुखी बनाने के लिए सतत् आधार पर वर्गीय एवं जनसंघर्षों को तथा सामाजिक मुद्दों पर संघर्षों को विकसित करने के साथ–साथ सांगठनिक गतिविधियों में आने वाले दिनों में गंभीर प्रयास करना होगा। इसके अन्तर्गत पार्टी सदस्यता की गुणवत्ता में सुधार तथा मास या जनलाइन के मद्देनजर पार्टी ब्रांचों के क्रियाकलापों में सक्रियता पैदा करना होगा। राजनीतिक एवं विचारधारात्मक स्तर को सशक्त करने के लिए ब्रांच सचिवों का क्लास एवं प्रशिक्षण का काम शुरू किया गया है। वर्ष 2023 में सदस्यता के नवीकरण के दौरान सदस्यता के लिए निर्धारित 5 सूत्रीय मापदंड को हमें सख्ती से लागू करना होगा।

हमारी पार्टी भारत के मजदूर वर्ग का क्रांतिकारी अगुआ दस्ता है। भारत की ठोस परिस्थितियों का अध्ययन करने के बाद पार्टी इस निष्कर्ष पर पहुँची है कि भारत में समाजवाद का रास्ता जनता की जनवादी क्रांति से होकर गुजरता है इसलिए जनवादी क्रांति पार्टी का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि एक जनक्रांतिकारी पार्टी का निर्माण किया जाय। इस काम को धरातल पर उतारने के लिए जनवादी केन्द्रीयता पर आधारित एक मजबूत और अनुशासित पार्टी की जरूरत है। यह काम पार्टी सदस्यों की गुणवत्ता में व्यापक सुधार कर ही हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।

चूँकि पार्टी सदस्य ब्रांचों/यूनिटों में संगठित होते हैं इसलिए ब्रांचों/यूनिटों के क्रियाकलापों में सक्रियता पैदा करना हमारा प्राथमिकता वाला कार्य है। पार्टी की झारखण्ड राज्य कमिटी ब्रांच सचिवों को सक्रिय करने और ब्रांचों की भूमिका को और विकसित किये जाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। □

23 दिसंबर 2022 को स्थानीय भाकपा कार्यालय में वाशिंग्टन पोस्ट में फॉरेंसिक संस्था अर्सेनल कंसलटेंसी की ओर से प्रकाशित खबर में फादर स्टेन स्वामी के लैपटॉप में हैक कर के 40 से ज्यादा मेल डालने की पुष्टि पर विभिन्न संगठनों की संयुक्त बैठक फादर टोनी की अध्यक्षता में हुई।

माकपा, भाकपा, भाकपा माले, राजद, माससं, साझा मंच, शाहिद स्टेन स्वामी न्याय मोर्चा के नेताओं ने एक मत हो कर असहमति के अधिकार के मुद्दे पर दीर्घकालिक अभियान के तहत अगले 3 महीने में 1000 छोटी सभाएं करने का निर्णय लिया। इसके लिए जनवरी की शुरूआत में एक वृहत संयुक्त बैठक की जाएगी।

इस मीटिंग के बाद अल्बर्ट एक्का चौक पर एक मानव शृंखला बनाई गई और नारे लगाए गए।

मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्र ने फिल्म ''पठान'' की अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ''टुकड़े–टुकड़े गैंग'' का सदस्य बताते हुए फिल्म के एक गाने में उनकी पोशाक के रंग को लेकर हंगामा बरपा दिया और उन्हें धमकी तक दे डाली। दूसरे मंत्री ने ''पठान'', जो फिल्म का नाम है, के देशभक्त होने पर ही प्रश्न खड़ा कर दिया।

01 जनवरी, 2018 को भीमा कोरेगांव में जातीय हिंसा की जांच कर रहे एक वरिष्ठ अनुमंडल पुलिस अधिकारी गणेश मोरे ने हिंसा की जांच के लिए गठित दो सदस्यीय न्यायिक आयोग के सामने शपथ के तहत स्वीकार किया है कि पुणे शहर से 30 किमी दूर आयोजित एल्गार परिषद कार्यक्रम की भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा में कोई भूमिका नहीं थी।

दूसरी ओर, वाशिंगटन पोस्ट में प्रकाशित फॉरेंसिक रिपोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि फादर स्टेन स्वामी के लैपटॉप में 2017 से 2019 की अवधि में हैक कर के 44 मेल प्लांट किए गए थे और उनकी गिरफ्तारी के एक दिन पहले तक हैकर ने अपने सबूत हटाए थे। 2014 से उनके लैपटॉप के 24000 फाइल भी निगरानी में थे। उन 44 प्लांट किए गए मेल से ही फादर स्टेन स्वामी का माओवादियों और एल्गार पारिषद केस से पुणे पुलिस और बाद में एनआईए ने सबंध स्थापित कर के उन पर यूएपीए लगाया और उन्हें जेल में डाला जहां 9 महीने बाद 5 जुलाई को उनकी मृत्यु हो गई। ये कोई समान्य आपराधिक घटना नहीं है, एक खतरनाक राजनीति है जिसे हम सभी को समझना चाहिए, बचना चाहिए, व्यापक जन समूह को आगाह करना चाहिए और विरोध करना चाहिए।

इस खतरनाक राजनीति को समझने के लिए हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। हिटलर के प्रबोधन और प्रचार मंत्री गोएबल्स का कहना था,

शेष पृष्ठ 3 पर .....

झारखंड की शिक्षा पर संकट - सर्वेक्षण की झलकियां

1. झारखंड में स्कूली शिक्षा प्रणाली शिक्षकों की कमी से जूझ रही है। नमूने या सैंपल में केवल 53 फीसद प्राइमरी स्कूलों और 19 फीसद अपर–प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित छात्र–शिक्षक अनुपात 30 से कम था।

2. सैंपल के 138 स्कूलों में से 20 फीसद में एक ही शिक्षक था। इनमें से ज्यादातर स्कूलों में एकमात्र शिक्षक पुरुष पारा शिक्षक हैं। इकलौते शिक्षक वाले स्कूलों में लगभग 90 फीसद विद्यार्थी दलित या आदिवासी बच्चे हैं।

3. प्राइमरी स्तर पर ज्यादातर शिक्षक (55 फीसद) पारा शिक्षक और अपर–प्राइमरी स्तर पर 37 फीसद पारा शिक्षक हैं। सैंपल में लगभग 40 फीसद प्राइमरी स्कूल पूरी तरह से पारा शिक्षक ही चल रहे हैं।

4. ज्यादातर स्कूलों के शिक्षकों का मानना है कि फरवरी 2022 में स्कूलों के फिर से खुलने तक ''अधिकांश'' छात्र पढ़ना–लिखना भूल गए थे।

5. सवेक्षण के दिन विद्यार्थियों की उपस्थिति (नामांकित बच्चों के मुकाबले उपस्थित बच्चे) प्राइमरी स्कूलों में केवल 68 फीसद और अपर–प्राइमरी स्कूलों में 58 फीसद थी।

6. सैंपल में शामिल एक भी स्कूल में न तो शौचालय था और न ही बिजली और पानी की आपूर्ति थी।

7. सैंपल के दो–तिहाई प्राइमरी स्कूलों में चारदीवारी नहीं थी, 64 फीसद में खेल का मैदान नहीं था और 37 फीसद में लाइब्रेरी की किताबें नहीं थीं।

8. बातचीत करने वाले ज्यादातर शिक्षकों (दो–तिहाई) ने कहा कि सवेक्षण के समय स्कूल के पास मिड–डे मील के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है।

9. कई स्कूल (शिक्षकों के मुताबिक 10 फीसद, सवेक्षण टीमों के मुताबिक इससे ज्यादा) अब भी हफ्ते में दो बार अंडे नहीं दे रहे हैं, जो तय किया गया था।

10. ज्यादातर सैंपल स्कूलों में, ''फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी'' (एफएलएन) सामग्री बांटने को छोड़कर, उन बच्चों की मदद के लिए खास कुछ नहीं किया गया जो कोविड–19 संकट के दौरान पढ़ना–लिखना भूल गए थे।

स्रोत झारखंड के 16 जिलों के 138 प्राइमरी और अपर–प्राइमरी स्कूलों का जीवीएसजे सवेक्षण, सितंबर–अक्टूबर 2022। इन सैंपल स्कूलों को 26 सैंपल ब्लॉकों के भीतर बेतरतीब ढंग से चुना गया था। इन स्कूलों में कम से कम 50 फीसद विद्यार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के हैं। □

हालात !

रेबिका की मौत पर घृणित राजनीति

साहेबगंज जिला के बोरियो में आदिवासी युवती रेबिका पहाड़िन का सिर विहीन शव के 18 से ज्यादा टुकड़ों को पुलिस ने बरामद किया और इस जघन्य हत्याकांड के 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अभी तक हत्या के कारणों का पता नहीं लगा पाई है। इस नृशंस हत्या में मुख्य आरोपी रेबिका का पति दिलदार अंसारी मुस्लिम समुदाय से है, अतरू इस मामले को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक रंग देने में लगी हुई है। राष्ट्रीय स्वयं संघ समर्थित जनजाति सुरक्षा मंच और वनवासी कल्याण केंद्र इसे लव जेहाद, धर्मांतरण और बांग्ला देशी घुसपैठिये से जोड़कर राज्य का माहौल खराब करने में लगी हुई है, साथ ही इस मामले में लड़कियों को भी जिम्मेदार मानते हुए उन को जाति, धर्म के अन्दर ही सीमित रहने की वकालत कर रही है।

यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि आदिवासी समेत तमाम समुदाय की लड़कियां कानूनी रूप से अंतर्जातीय और अंतरधार्मिक विवाह करने के लिए स्वतंत्र हैं और बढ़ती जागरूकता और घटती रूढ़ीवादिता एवं दहेज जैसे बर्बर कारणों से ऐसे विवाहों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

आरएसएस और उस के अनुषंगी भाजपा, विहिप जैसे धुर सांप्रदायिक संगठन जो धार्मिक कट्टरता, रूढ़िवादिता, नारी पराधीनता, पुरूष वर्चस्व, अशिष्टता और असभ्यता के समर्थक हैं, ने फौरन रेबिका पहाड़िन की नृशंस हत्या को लव जेहाद, घुसपैठिये, धर्मांतरण जैसे संघ परिवार के सांप्रदायिक एजेंडे से जोड़ दिया और इसे एक नया रंग देने में लग गए जब कि पुलिस अब तक हत्या के कारणों को नहीं खोज पाई है।

यहां दो बातें महत्तवपूर्ण हैं। पहला रेबिका पहाड़िन की बर्बर हत्या एक विशुद्ध आपराधिक मामला है जिस के लिए दोषियों को विधि सम्मत कठोरतम दंड मिलना चाहिए, जो हमारी भी मांग है।

दूसरे, इस आपराधिक घटना को सांप्रदायिक रंग देने वाले संघ परिवार को भी कानूनी दायरे में ला कर उसे कठघरे में खड़ा करना चाहिए तथा समाज में रेबिका पहाड़िन की लाश पर भी राजनीति करने वाले उसके घृणित सांप्रदायिक चेहरे को उजागर करना चाहिए। □

माकपा का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर जामताड़ा में

माकपा का दो दिवसीय राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शिविर 4 एवं 5 फरवरी को जामताड़ा में आयोजित होगा। इस प्रशिक्षण शिविर में राष्ट्रीय – अंतरराष्ट्रीय स्थिति और आंदोलनों का अद्यतन आकलन, झारखंड में पिछले राज्य सम्मेलन और पार्टी काँग्रेस के आलोक में हुए कार्यों की समीक्षा और संगठन पर विस्तृत चर्चा होगी। इस शिविर में पूरे राज्य से लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे।

पीपुल्स कोऑपरेटिव कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन

झारखंड राज्य सहकारिता के क्षेत्र में पिछड़े राज्यों में गिना जाता है जब कि इस क्षेत्र में संभावनाएं आपार हैं. केरल, महाराष्ट्र, गुजरात आदि कई राज्य के लोग सहकारिता अभियान से जबरदस्त तरीके से लाभान्वित हो रहे हैं।

हमारे झारखंड में कई क्षेत्रों, विशेष कर के कृषि और शिक्षा के क्षेत्र में, सहकारिता द्वारा राज्य की मेहनतकश जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है।

इसी उद्देश्य से ''सहकारिता का महत्व और उसका उपयोग'' विषय पर चर्चा के लिए एक मीटिंग रविवार, 11 दिसंबर 2022 को सुबह 11 बजे से सफदर हाशमी सभागार, CPI(M) राज्य कार्यालय, विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची में संपन्न हुई जिसमें राज्य भर से 20 प्रमुख लोगों ने भाग लिया।

मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए कोऑपरेटिव विशेषज्ञ भंते जैनेन्द्र कुमार तथागत ने समाज के अंतिम पायदान तक के लोगों की बेहतरी के लिए कोऑपरेटिव अभियान की महता के बारे में विस्तार से बातें रखीं। कोऑपरेटिव अभियान के इतिहास और उसकी अभी तक के विकास यात्रा के बारे में अमूल के उदाहरण के साथ अपनी बातें रखी। उन्होंने बताया कि कोऑपरेटिव कैसे वस्तुओं का मूल्य संवर्धन करके अपने सभी सदस्यों का जीवन स्तर उठाती है और समाज को भी समृद्ध करती है।

मीटिंग को संबोधित करते हुए माकपा राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने केरल को उधृत करते हुए वहां के विकास में कोऑपरेटिव अभियान के महती योगदान को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव अभियान कॉरपोरेट हमले का सामना करने में सक्षम है।

माकपा राज्य केंद्र के अमल पांडेय ने पीपुल्स कोऑपरेटिव कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के गठन का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। मीटिंग में उपस्थित सभी सदस्यों ने नव गठित संगठन की सदस्यता ली।

प्रकाश विप्लव परामर्शदातृ मंडल के चेयरमैन, भंते जैनेंद्र कुमार तथागत अध्यक्ष, संतोष कुमार कार्यकारी अध्यक्ष, अमल पांडेय महासचिव और बीरेन्द्र कुमार कोषाध्यक्ष चुने गए। इसके अलावे 3 उपाध्यक्ष, एक संयुक्त सचिव और दो सचिव भी चुने गए।

पीपुल्स कोऑपरेटिव कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन के बाइ लॉज बनाने की जिम्मेवारी महा सचिव को दी गई।

अगले 60 दिनों में सभी जिलों में संगठन विस्तार का निर्णय लिया गया तथा अधिक से अधिक सदस्यता और संबद्धता पर जोर दिया गया।

पार्टी के सभी स्तरों पर विशेषकर किसान सभा को कृषि उत्पादन, वितरण और बाजार के क्षेत्र में कॉपरेटिव बनाने की दिशा में ठोस पहल करना जरूरी है। □

– अमल पांडे

48वाँ शहादत दिवस

27.12.2022 को चासनाला कोलियरी के शहीद स्मारक स्थल में 48वाँ शहादत दिवस मनाते हुए सभी 375 मजदूरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया।

दोपहर 1.35 बजे सायरन के साथ 2 मिनट का मौन धारण किया गया उसके बाद पुष्प माला अर्पित किया गया। ज्ञात हो कि 27 दिसंबर 1975 को प्रबंधन की भूल के कारण 375 मजदूरों की जल समाधि हो गई थी। यह एशिया की सबसे बड़ी खान दुर्घटना थी। श्रद्धा सुमन अर्पित करने वालों में सेल प्रबंधक एवं बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के कॉ0 सुंदर लाल महतो, कॉ0 योगेंद्र महतो, कॉ0 कार्तिक ओझा, कॉ0 अरुण यादव, कॉ0 शक्तिपदा महतो, कॉ0 समीर मंडल, कॉ0 चंद्र नाथ घोष, अजीत कुमार महतो, विकास कुमार रंजन, रज्जप अंसारी, मदन दास, जगदीश महतो, पदों रजक, विक्की महतो, महेश महतो, अखिलेश साहू, जवाहरलाल महतो, सोनू महतो, भोलू महतो इत्यादि शामिल थे। □

पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ एडवा का आंदोलन

धनबाद के सिंदरी में डीनोबिली स्कूल के छात्र अस्मित अकाश की रहस्यमय मौत के दस माह बीतने के बाद भी अपराधियों पर कोई कारवाई नहीं होने तथा पुलिस द्वारा इस मुद्दे पर गोल–मटोल जवाब दिये जाने के खिलाफ एवं सिंदरी में बढ़ते अपराध और पुलिस की निष्कृयता के खिलाफ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (एडवा) द्वारा आक्रोश मार्च निकाल कर सिंदरी थाना पर विक्षोम प्रदर्शन किया गया और दो घंटे तक सिंदरी थाना का घेराव किया गया।

प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए एडवा के राज्य महासचिव वीणा लिंडा ने सिंदरी पुलिस पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि दस माह में भी छात्र अस्मित आकाश की मौत का खुलासा नहीं होने से पुलिस प्रशासन के प्रति आम जनता में गहरा आक्रोश है। □

जोमैटो डिलीवरी वर्कर्स का पब्लिक अपील पखवाड़ा

रांची के मोराबादी स्थित ऑक्सीजन पार्क में 22 दिसम्बर को जोमैटो के भोजन डिलीवरी कामगारों ने ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बैठक की। बैठक में सीटू के राज्य महासचिव बिस्वजीत देब, कोषाध्यक्ष अनिर्बाण बोस उपस्थित रहे।

बैठक में तय कार्यक्रम के अनुसार जोमैटो डिलीवरी वर्कर्स अपने ग्राहकों और आम जनता को अपनी पीड़ा और प्रबंधन के अमानवीय शोषण से अवगत कराने के लिए जोमैटो डिलीवरी वर्कर्स 25 दिसंबर से 7 जनवरी तक श्पब्लिक अपील पखवाड़ा मना रहे हैं। इस दौरान वो पर्चा वितरण कर अपनी समस्याओं के बारे में अपने ग्राहकों को अपनी स्थिति से अवगत करा रहे हैं. 6 जनवरी को हैशटैग जोमैटो ग्राहक जोमैटो डिलीवरी कर्मचारी के साथ डिलीवरी वर्कर्स के पक्ष में सोशल मीडिया अभियान चलाने की भी अपील कर रहे हैं।

जोमैटो के डिलीवरी कर्मचारी रांची के श्रम विभाग में प्रबंधन और उनकी यूनियन ऑल इंडिया गिग वर्कर्स यूनियन के बीच चल रही त्रिपक्षीय सुलह की कार्यवाही के शीघ्र तार्किक निष्कर्ष की उम्मीद कर रहे हैं। बैठक में राज्य सचिव प्रतीक मिश्रा और अध्यक्ष रोहित के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद थे। □

असहमति की संस्थागत ...

..... शेष पेज 1 का

''अगर सत्ता द्वारा बड़ा झूठ लगातार बोलते रहा जाए तो जनता अंततः उस झूठ को सच मान लेगी। लेकिन ऐसे झूठ तब तक ही कायम रखे जा सकते हैं जब तक इन का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम सच के रूप में जनता के सामने नहीं आ जाता। इसीलिए सत्ता पूरी ताकत से किसी भी सीमा तक जा कर असहमति / विरोध को कुचल कर सच को उजागर होने से रोकती है। ये सब जानते हैं कि सच झूठ का दुश्मन है, इसका पर्याय ये भी है कि सत्ता सच की दुश्मन है''।

प्रश्न ये उठता है कि असहमति का राजनीतिक–सामाजिक अर्थ क्या है? न मौन ही असहमति है और न ही ड्रॉइंग रूम में बैठ कर चर्चा भर कर लेना ही असहमति है। असहमति है जनता के बीच में अपनी असहमति का प्रकटीकरण, चाहे वो लेखन, वाचन या संघर्ष/ आंदोलन जैसे किसी भी माध्यम से हो। प्रश्न ये भी है कि असहमत कौन होगा? जाहिर है, जो मुद्दों और नीतियों की देश के संविधान के अनुरुप समझ और उन पर पकड़ रखेगा वही असहमत होगा। उसे आम तौर पर जागरुक नागरिक, बुद्धिजीवी, वैचारिक प्रतिबद्धता से लैस इंसान, आलोचक, विद्रोही आदि नामों से संबोधित किया जाता रहा है। सत्ता की जनविरोधी नीतियों और क्रिया–कलापों का ये लोग ही सतत विरोधी रहे हैं, इन जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलनों के वैचारिक अगुआ रहे हैं, सत्ता के झूठ का पर्दाफाश करते रहे हैं। चूंकि ये सत्ता की झूठ के खिलाफ खड़े रहते हैं इसीलिए ये सत्ता विरोधी करार दिए जाते हैं। निरंकुश सत्ता खुद को राष्ट्रभक्त घोषित करती रहती है तो सत्ता विरोधी होने के कारण असहमति रखने वाले सभी लोगों को राष्ट्रद्रोही घोषित करती रहती है। फिर क्या, सत्ता खुद और अपने सहस्त्र अनुषंगी इकाईयों, मीडिया, संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तकनीक और प्रौद्योगिकी आदि सबका समुचित दुरूपयोग कर के असहमति रखने वालों, विरोधियों के खिलाफ जहर उगलने, उनका चरित्र हनन करने, षडयंत्र कर के उनको कानून के मकड़जाल में फंसाने और उनकी हत्या तक करने में कोई हिचक नहीं रखते हैं।

ऐसा ही हिटलर की जर्मनी में होता था और ऐसा ही अब हमारे देश में भी हो रहा है। कलबुर्गी, दाभोलकर, गौरी लंकेश असहमति के परिणामों के उदाहरण हैं। 2014 में बड़े घोटालों और स्वप्निल वादों के विशाल झूठे प्रचार पर केंद्र में आई भाजपा सरकार का ''अच्छे दिन'' का तिलिस्म जब टूटने लगा और देश के बुद्धिजीवी और वैचारिक रूप से जागरूक नागरिक जब झूठ का पर्दाफाश करने लगे तो वे सत्ता के निशाने पर आ गए और सत्ता इन पर अपनी पूरी ताकत से टूट पड़ी।

जनता के सवालों से चिढ़ने वाले, मुद्दों और नीतियों पर सवाल उठाने वालों तक से चिढ़ने लगे, जनता की बात सुनने के जगह मन की बात सुनाने लगे, जनता का एजेंडा लागू करने की जगह आरएसएस का एजेंडा लागू करने लगे। महँगाई, रोजगार, गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, देश निर्माण, भ्रष्टाचार, अन्याय आदि सभी प्रमुख मुद्दों पर केंद्र सरकार के यू टर्न लेने के कारण जनता त्राहिमाम करने लगी तो जनता का आक्रोशित होना स्वाभाविक था और बुद्धिजीवी और जागरूक नागरिकों का आवाज बुलंद करना भी लाजमी था। सत्ता के शुरुआती चरण में ही भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 का व्यापक जनविरोध के कारण सरकार का अध्यादेश वापस लेने को मजबूर होना तानाशाही के मुँह पर एक करारा तमाचा था। रोहित वेमुला से जेएनयू तक 2016–17 की अवधि में देशद्रोही और टुकड़े–टुकड़े गैंग का संबोधन सत्ता विरोधियों के लिए आम हो चुका था। अक्टूबर 2018 में सरकार ने एक हिंदुत्व वादी अमेरिकी स्कॉलर राजीव मल्होत्रा को जेएनयू का अवैतनिक प्रोफेसर नियुक्त किया जिसने नैरेटिव दिया कि ''देश के असली दुश्मन देश में रह रहे बुद्धिजीवी हैं जिनका काम सिर्फ देश की कमियां गिनाना, देश को बदनाम करना है''। तत्कालीन केंद्रीय मंत्री ने तो उसी वर्ष 21 खयाली देशद्रोही बुद्धिजीवी संगठनों की एक सार्वजानिक कार्यक्रम में निंदा भी की। पिट्ठू विवेक अग्निहोत्री ने ''अर्बन नक्सल'' का स्लोगन दिया जिसे सत्ता ने बुद्धिजीवियों के लिए व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया।

2018 के ही एल्गार पारिषद केस में गोएबल्स की उक्ति का केंद्रीय सत्ता ने जबरदस्त प्रयोग किया और देश भर से 16 प्रख्यात सामाजिक हस्तियों को आतंकवाद, देशद्रोह और हत्या की साजिश जैसे संगीन आपराधिक धाराओं में यूएपीए तक लगाया और उन्हें फंसा कर जेल में डाल दिया।

असहमति / विरोध की राजनीति को समझने के लिए फादर स्टेन स्वामी का जीवन एक सटीक उदाहरण है। धर्म के ज्ञाता स्टेन न्याय, मानवता और सच के साथ खड़े होने को ही असली धर्म मानते थे। आदिवासियों के जमीन से जुड़े मुद्दों पर वे बहुत सचेत रहते थे और उन्हें लगातार सचेत करते भी रहते थे। धार्मिक विद्वेष के वातावरण से दुःखित थे। माओवादी – नक्सली होने के आरोप में झारखंड के जेलों में सालों से बंद हजारों कैदियों को इंसाफ दिलाने की मुहिम में भी वे लगे थे। इसके लिए उन्होंने Persicuted Prisoners Solidarity Committee (PPSC) का गठन किया जिसके माध्यम से उन्होंने 102 बेल पाए कैदियों से बात की और उनमें से 99 का माओवाद – नक्सलवाद से कोई रिश्ता नहीं पाया था। केंद्र सरकार ने उनके इसी काम के आधार पर उन्हें माओवादी करार दे कर PPSC को माओवादियों के लिए कोष संग्रह करने वाला संगठन बताया था। वे सत्ता के जनविरोधी नीतियों के प्रखर विरोधी भी थे। ये सब भला निरंकुश सत्ता को कैसे बर्दाश्त होता? उनका अंजाम हम सब जानते हैं। एल्गार पारिषद केस के बाकी 15 आरोपियों का भविष्य अधर में है। हाल में राष्ट्रपति का बयान ''विकास की इतनी बातों के बावजूद देश में और जेलों की आवश्यकता क्यूँ है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए'' एक सकारात्मक बयान है।

मार्टिन निमोइलर एक जर्मन लूथरन पादरी और धर्मविज्ञानी थे। वे कम्युनिस्ट–विरोधी और एडॉल्फ हिटलर के समर्थक थे। हिटलर ने धर्म पर राज्य की सर्वोच्चता पर जोर दिया, जिससे निमोइलर निराश हो गए और वह हिटलर के विरोध में जर्मन पादरी के एक समूह के नेता बने। 1937 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें 1945 में सहयोगियों द्वारा छुड़ाया गया था और बाद में वे फासीवाद के विरोधी बने रहे।

एक तरफ सवाल करना और असहमति दिखाना / विरोध करना आज देशद्रोह जैसा हो गया है तो दूसरी तरफ निरंकुश – तानाशाह सत्ता संविधान और संवैधानिक संस्थाओं को ताक पर रख कर जनविरोधी और नफरती नीतियों को तेजी से लागू करने में लगी है। हमें देश के सर्वोच्च अधिकार संपन्न नागरिक से अधिकार विहीन प्रजा बनाने पर उतारू है।

हम ऐसा होने नहीं देंगे. हम अपनी ताकत के अनुसार प्रतिरोध मे हैं। एक हो कर हर स्तर पर निरंकुश सत्ता की इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे, इस साजिश के विरुद्ध व्यापक गोलबंदी कर के इस क्रूर सत्ता को पराजित करेंगे। यही सच्चा देशप्रेम है, सच्ची देशभक्ति है। आईए इस पुनीत काम में प्रणप्राण से लगें। □

प्रज्ञा केन्द्र संचालकों की बैठक

राज्य के हर पंचायत में एक डिजिटल सेवा केंद्र (झारखंड में ''प्रज्ञा केंद्र'') होता है, जिसे भारत सरकार की डिजिटलीकरण योजना के तहत शुरू किया गया था। इसके संचालकों को एक खास नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था और चयनित व्यक्ति को अपने स्वयं के खर्च पर अपने केंद्र स्थापित करने की अनुमति दी गई थी, उन्हें प्रत्येक पंचायत में सरकार के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एकमात्र अधिकृत केंद्र माना जाता है।

अब पूरी प्रक्रिया को निजी एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया गया है एवं कोई सरकारी हस्तक्षेप, जांच और नियंत्रण के बिना उस एजेंसी द्वारा 'सरकारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के लिए बेतरतीब ढंग से नई नई नियुक्तियां की जा रही है, जिसे 'कॉमन सर्विस इ सेंटर' के रूप में अधिकृत किया जा रहा है।

इस बदली हुई व्यवस्था से न केवल मौजूदा प्रज्ञा केंद्र एकमात्र सरकारी अधिकृत एजेंसी के रूप में अपनी मान्यता और महत्व खो चुके हैं, बल्कि अनियंत्रित संचालन के कारण धोखाधड़ी का दायरा भी कई गुना बढ़ गया है। इसके कारण प्रज्ञा केन्द्रों के संचालकों पर अब रोजी–रोटी का संकट भी मंडराने लगा है।

झारखंड सरकार इन ऑपरेटरों को कोई मानदेय नहीं दे रही है, जबकि कई अन्य राज्य सरकारें मानदेय की राशि का भुगतान करती हैं।

इस पृष्ठभूमि में इन केन्द्रों के संचालक देश भर में संगठित हो रहे हैं, कुछ राज्यों में उनकी ट्रेड यूनियनें पंजीकृत भी हो गई हैं। पश्चिम बंगाल आदि में उनके यूनियन को सीटू की संब)ता भी मिल गई है।

अखिल भारतीय स्तर पर भी सीटू के मार्गदर्शन में 'ऑल इंडिया आधार ऑपरेटर यूनियन' का गठन किया गया है। झारखंड में अनुमानित 4500 ऐसे ऑपरेटर हैं और 19 जिलों में वे संगठित भी हैं।

रांची के स्टेट सेंटर में हाल ही में सीटू के राज्य नेतृत्व के साथ इन ऑपरेटरों के नेतृत्व की एक बैठक हुई जिस में निर्णय लिया गया कि –

1. यूनियन का नाम 'झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन' होगा।
2. सीटू का राज्य केंद्र उनके ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने और सीटू की संबद्धता प्राप्त करने की प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन और उनकी मदद करेगा।
3. सभी जिलों में सीटू की समितियाँ इन संचालकों को भविष्य की सांगठनिक और आंदोलनात्मक गतिविधियों के लिए सहयोग

शेष पृष्ठ 4 पर .....

समझ का नफरत के खिलाफ मुहिम

साझा मंच झारखंड (समझ) द्वारा 28.11.2022 से एक पखवारे तक रांची के संत जॉन, होली क्रॉस, मिल्लत एकेडेमी और भुरकुंडा के पावन क्रूस और अग्रसेन स्कूलों के 1500 विद्यार्थियों और 30 शिक्षक–शिक्षिकाओं के बीच धार्मिक–जातीय नफरत की मुहिम के खिलाफ और वैज्ञानिक चेतना के साथ संविधान की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से लघु फिल्मों के प्रदर्शन का कार्यक्रम चलाया गया।

प्रख्यात फिल्मकार अखरा के कॉम मेघनाथ के कुशल निर्देशन और उनके सक्रिय भागीदारी ने बच्चों के बीच इस कार्यक्रम को बेहद रोचक बना दिया।

शेष पृष्ठ 4 पर .....

चौपाल

बंदर ने कहा
मुझे कोई नहीं
पकड़ सकता,
मेरा कोई कुछ नहीं
बिगाड़ सकता,
मैं ऊंची छलांग
लगाऊंगा,
तुम्हें नई दुनिया में
ले जाउंगा.

बंदर को जबरदस्त
वोट मिले
बंदर राज्याध्यक्ष बने
जंगल को नए राजा मिले.
बकरी पहुंची लेकर गुहार,
शेर मेरा बच्चा ले गया सरकार.
बंदर पूरी शिद्दत से लगा कूदने,
दरबारी उसके सब लगे झूमने.

शेर ने इधर मेमने का काम तमाम किया,
उधर बकरी ने चक्का जाम किया.
मीडिया बरस रही अब बकरी पर,
जज बरस रहा जनता की असुविधा पर.
बकरी की मांग थी, बंदर आए,
मुझको मेरा मेमना लौटाए.
बंदर तब टीवी पर आया,
कातर स्वर मे उसने बतलाया.....

जब से मेमने की कथा सुना हूं,
बंदर की तरह कूद–फांद रहा हूँ,
भूख–नींद सब तज दिया है,
टीवी से एक मिनट भी नहीं हटा हूँ,
फिर भी अगर बकरी को शक है,
तो ये शक मुझ पर नाहक है.
मेरी मेहनत पर कोई शक हो तो वो बोले,
वर्ना राष्ट्रद्रोही होने का अपना रस्ता खोले....

जन स्वास्थ्य अभियान की बैठक

जन स्वास्थ्य अभियान की बैठक राज्य कार्यालय में 25.12.2022 को कॉम किशोर चक्रवर्ती की अध्यक्षता मे हुई जिस में शहरी क्षेत्रों के स्लम और गरीब मोहल्लों में स्वास्थ्य और आरोग्य के प्रति जागरूकता और निदान विषय पर चर्चा हुई। चर्चा की शुरुआत पीपल्स साइंस फोरम के सचिव सुभाष चटर्जी की रिपोर्टिंग से हुई जिसमें उन्होंने डिबडीह मुहल्ले में प्रस्तावित मेडिकल कैम्प के बारे में ब्योरा रखा।

जन स्वास्थ्य अभियान के उद्देश्यों पर एक विस्तृत रिपोर्ट स्लाइड के माध्यम से माकपा राज्य केंद्र के अमल पांडेय ने रखा जिसमें आरोग्य और रोग निदान के बारे में बिन्दुवार बातें थीं. आरोग्य के लिए सावधानियों से ले कर, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सरकारी जिम्मेवारियों के बारे में ठोस बिंदु तय किए गए। अच्छी–बुरी स्वास्थ्य संबंधी आदतों पर भी विचार हुआ।

दीर्घावधि आरोग्य के लिए स्वास्थ्य कार्ड बनाने की जिम्मेदारी अमल पांडेय और साझा मंच के सुधांशु शेखर को दी गई। आगामी 8 जनवरी को डिबडीह के पार्षद से मिलने का कार्यक्रम लिया गया। बैठक में बीएसएसआर यूनियन से एजाज और रूपेश और पीएसएफ से रवि भी शामिल थे। □

तस्वीरों में कार्यक्रम ...

गोमिया अंचल किसान सभा का सम्मेलन

ठेका मजदूर यूनियन, सिन्दरी

बेफी महिला मोर्चा का सम्मेलन, राँची

एडवा, साहेबगंज

किसान आंदोलन, बोकारो

एडवा, सिन्दरी

एसएफआई, धनबाद

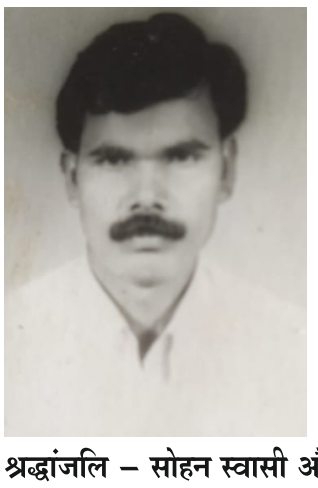

श्रद्धांजलि – सोहन स्वासी और गुलाब हजाम, राहे लोकल कमेटी

आगामी कार्यक्रम

किशोर वाहिनी की राज्य स्तरीय कार्यशाला और सम्मेलन 12–13 फरवरी को मैथन में।

प्रज्ञा केन्द्र .....

..... शेष पृष्ठ 3 का

करेंगी।

4. संगठनात्मक और आंदोलनकारी कार्यों की चरणबद्ध योजना बनाई गई है, जिसकी समय–समय पर सीटू राज्य केंद्र द्वारा समीक्षा, सहयोग और निगरानी की जाएगी। □

– प्रतीक

समझ का .....

..... शेष पृष्ठ 3 का

बच्चों के मन पर गहरी छाप छोड़ने वाली संवेदनशील फिल्में और उनके बाद उनका सामुहिक विश्लेषण और उनसे मिलती सीख विद्यार्थियों – शिक्षक–शिक्षिकाओं के साथ ही साझा मंच और स्कूल प्रबंधन के लिए भी एक विस्मयकारी सुखद अनुभव था।

फिल्मों के बाद उनकी सामुहिक समीक्षा और फिर संविधान की प्रस्तावना का सामुहिक पाठ से साथ कार्यक्रम की समाप्ति अविस्मरणीय अनुभव रहा।

इस कार्यक्रम आयोजन और संयोजन में मेघनाथ जी के अलावे साझा मंच के नंदिता भट्टाचार्य, फादर टॉम, फादर टोनी, समीर दास, सरफराज, सुधांशु शेखर, प्रफुल्ल लिंडा और अमल पांडेय की उल्लेखनीय भूमिका रही। □

पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

Communist Party of India Marxist
Bank : Bank of Baroda
Main Branch, Ranchi
A/c No. : 00170200000219
IFSC Code : BARB0RANCHI

सीपीआई (एम) राज्य कमिटी, झारखण्ड की ओर से राज्य सचिव प्रकाश विप्लव द्वारा संपादित एवं प्रेषित। संकलन एवं संयोजन सुधांशु शेखर, अमल पाण्डेय व बिपिन कु0 सिन्हा।
माकपा पार्टी कार्यालय : विश्वकर्मा मंदिर लेन, मेन रोड, रांची–834001, वेबसाईट : cpimjharkhand.org, ई–मेल : janjohar.jharkhand@gmail.com